

धसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उपलण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381]

नद्वै विल्ली, मंगलवार, ग्रगस्त 24, 1976/भाव 2, 1898

No. 381]

NEW DELHL, TUESDAY, AUGUST 24, 1976/BHADRA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह धलग संकलन के कप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August 1976

- S.O. 563(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and seventeenth Amendment) Rules, 1976.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule,—
 - (i) for entry 1B, the following entries shall be substituted, namely:—
 - "1B. Ministry of Civil Supplies and Cooperation (Nagrik Poorti aur Sahakarita Mantralaya).
 - 1C. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya):
 - (i) Department of Foreign Trade (Videsh Vyapar Vibhag).
 - (ii) Department of Export Production (Niryat Utpadan Vibhag).
 - (iii) Department of Textiles (Vastr Vibhag).";

- (ii) for entry 10, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "10. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya):
 - (i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).
 - (ii) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).";
- 3. In the Second Schedule to the said rules,-
 - (i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)", in the entries under the subheading "C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)", the following entry shall be added at the end, namely:—
 "10. Public Cooperation,";
 - (ii) after the heading "MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—
 - "MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHAKARITA MANTRALAYA)

I. INTERNAL TRADE

- 1. Internal Trade.
- Inter-State Trade; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.
- 3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].
- 4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

II. TRADE MARKS, ETC.

- 5. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958,
- 6. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.
- 7. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).
- All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any
 of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

III. CO-OPERATION

- General policy in the field of Co-operation and co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Cooperatives in their respective fields).
- 10. Matters relating to National Co-operative Organisations.
- 11. National Co-operative Development Corporation.
- Incorporation, regulation and winding up of co-operative societies with objects not confined to one State.
- 13. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).
- 14. Consumer Co-operatives.
- 15. Public Distribution System.
- 16. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
- 17. The National Consumer Protection Council.
- 18. Regulation of packaged commodities.
- 19. Training in Legal Metrology.
- 20. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.";
- (iii) for the heading "MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (UDYOG AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely:—
 - "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)";

- (iv) under the heading as so substituted,-
 - (a) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOP-MENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)" in entry 24, the words, brackets and figures "the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952" shall be omitted;
 - (b) the sub-heading "C. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA VIBHAG)" and the entries thercunder shall be omitted.

F. A. AHMED, Prosident.

[No. 74/2/6/76-CF]
J. S. MONGIA, Addl. Secy.

मंत्रीमंडन सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1976

- का० भा० 563(भ).—राष्ट्रपति, संविधान के भ्रनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त गितियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्ये-म्रावटन) नियम, 1961 में ग्रीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, भ्रथीत् :—
- 1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-प्रःवंटन) (एक सौ सवहवा सशोधन) नियम, 1976 है।
 - (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत सरकार (कार्य-श्रांबटन) नियम 1961, (जिनको इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) मे, प्रथम श्रनुसूची मे,--
 - (I) प्रविष्टि 1 ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जामेगी, अर्थात् :--"1 ख. नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय।
 - 1. ग. वाणिज्य मंत्रालय:
 - (i) विदेश व्यापार विभाग ।
 - (ii) निर्यात उत्पादन विभाग ।
 - (iii) वस्त्र विभाग।";
 - (II) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, ग्रर्थात् ——
 "10. उद्योग मंत्रालय:
 - (i) भौधोगिक विकास विभाग।
 - (ii) भारी उद्योग विभाग";

- 3. उक्त नियमों की ब्रितीय प्रनुसूची में,---
 - (i) "कृषि श्रौर सिंचाई" शिर्षक के श्रांतर्गत, उभयीर्षक "ग. ग्रामीण विकास विभाग" के श्रन्तर्गत प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टि श्रन्त में जोड़ी जाएगी, श्रथीत् :---"10 लोक सहकारिता।";
 - (ii) ''रसायन और उर्वरक मंत्रालय'' शीर्षक और उसने श्रंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक श्रौर प्रविष्टियां श्रंतः स्थापित की जाएंगी, श्रर्थात् :---

''नागरिक पूर्ति श्रीर सहकारिता मंत्रालय

1. ग्रान्तिरिक व्यापार

- ग्रान्तरिक व्यापार ।
- भ्रन्तर्राज्यिक व्यापार ; स्पिरिटयुक्त निर्मिति (भ्रन्तरीज्यिक व्यापार श्रीर वाणिज्य) नियंत्रण श्रीधनियम, 1955.
- वायदा व्यापार का नियंत्रण [ग्रिग्रिम संविदा (विनियमत) ग्रिधिनियम, 1952]
- भावश्यक वस्तु भ्रधिनियम, 1955 (ऐसी म्रावश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें ग्रौर वितरण, जिनसे विनिर्दिष्टत: कोई म्रन्य मंत्रालय संबद्ध नहीं है)।

2. व्यापार चिक्क, मावि

- 5. व्यापार श्रीर पण्य वस्तु चिह्न ग्रधिनियम, 1958.
- 6. संप्रतीक ग्रौर नाम का (श्रनुचित प्रयोग निवारण) श्रधिनियम, 1950.
- बाट ग्रीर माप मानक (बाट ग्रीर माप मानक ग्रिधिनियम, 1956—बाट ग्रीर माप मानक ग्रिधिनियम, 1976) ।
- 8. इ.स. सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न या श्रधीनस्थ कार्यालय या श्रन्य संगठन, जिनमें वायवा बाजार श्रायोग, मुम्बई भी सम्मिलित है।

3 सहकारिता

- 9. सभी क्षेत्रों में सहकारिता श्रीर सहकारी किया-क्लापों के समन्वय के क्षेत्र में सामान्य नीति (संबंधित मंत्रालय श्रपने श्रपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाश्रों के लिए उत्तर-दायी है) ।
- 10. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित विषय ।
- 11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
- 12. ऐसी सहकारी संस्थाओं का, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।
- 13. सहकारी विभागों श्रीर सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों श्रीर गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है)।
- 14. उपभोक्ता सहकारी संस्थायें।

- 15. लोक वितरण प्रणाली ।
- 16. कीमतों का परिवीक्षण ग्रौर ग्रावश्यक वस्तुश्रों की उपलभ्यता।
- 17. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।
- 18. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन
- 19. कान्नी माप-विद्या मे प्रशिक्षण।
- 20. भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिह्नन) ग्रिधिनियम, 1952";
- (iii) ''उद्योग भीर नागरिक पूर्ति मंत्रालय'' शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, भ्रर्थात् :--

"उद्योग मंत्रालय" ;

- (iv) इस प्रकार प्रतिस्थापित शीर्षक के धन्तर्गत,---
 - (क) उप-शिर्थक "क श्रौद्योगिक विकास विभाग" के श्रन्तर्गत प्रविष्टि 24 मे, "भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिह्नन) श्रिधिनियम, 1952" णब्दों, कोष्ठकों श्रीर श्रंकों का लोप कर दिया जाएगा ;
 - (ख) उप-णीर्षक ''ग. नागरिक पूर्ति श्रीर सहकारिता विभाग'' श्रीर उसके श्रन्तंगत श्रोनेवाली प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

फखरुद्दीन ग्रली श्रहमद, राष्ट्रपति ।

[स॰ 74/2/6/76-सी एफ॰] जे॰ एसः मोगिया, श्रपरसचिव।

